वैगन इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण

4342. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, वैगन इंडिया लिमिटेड को वैगन बनाने के लिए सामग्री प्रदान करता है;

(ख) वैगन इंडिया लिमिटेड, वैगनों के निर्माण के लिए श्रम पर कितने प्रतिशत व्यय करता है और इस संबंध में संस्थापन व्यय कितने प्रतिशत है; और

(ग) वैगन इंडिया लिमिटेड को रेलवे वैगनों के निर्माण पर सामग्री और श्रम संबंधी कितनी-कितनी लागत आती है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) वैगन इंडिया लिमिटेड एक आपूर्ति करने वाली कंपनी है जो कि रेलवे से वैगनों के आदेश प्राप्त कर अपने शेयर धारक सदस्य कंपनियों को वितरण करती है। यह रेलवे से कोई सामग्री प्राप्त नहीं करती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन इंडिया लिमिटेड द्वारा वैगनों का निर्माण किया जाना

4343. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैगन इंडिया लिमिटेड की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है;

(ख) वैगन इंडिया लिमिटेड में कितने अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं और वर्ष 1997-98 में उन पर कितना संस्थापन व्यय किया गया; और

(ग) क्या वैगन इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए रेलवे वैगनों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है; यदि हां, तो लक्ष्य क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) वैगन इंडिया लिमिटेड की स्थापना करने का एक मात्र उद्देश्य रेलवे से मुख्य रूप से वैगन के आदेश प्राप्त करना और जो इसके शेयर होल्डर हैं, को समान रूप से वैगन के निर्माताओं को वितरित करना था।

(ख) इस समय वैगन इंडिया लिमिटेड में 6 अधिकारी और 7 अन्य कर्मचारी हैं। कंपनी ने 1997-98 के दौरान कुल 43.16 लाख रुपये खर्च किए थे।

(ग) चूंकि वैगन इंडिया लिमिटेड वैगन उद्योग के लिए एक सर्विस संगठन है और वैगनों का निर्माण नहीं करती है इसलिए 1998-99 के दौरान डब्ल्यू आई एल द्वारा वैगनों के निर्माण को जारी रखने का प्रश्न नहीं उठता।

आयात नीति का उदारीकरण

4344. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयात नीति को और ज्यादा उदार बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले में आयात नीति को उदार बनाया गया है;

(ग) इस आयात नीति का घरेलू लघु तथा कुटीर उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या इस आयात नीति के परिणामस्वरूप उपर्युक्त घरेलू उद्योग पनपेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो किस तरह और यदि इन्हें धक्का पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में इन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने 13.4.1998 को 340 और मदों का निःशुल्क आयात करने की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) निःशुल्क आयात सूची में परिवर्तित की गई 340 मदों में से केवल 57 मदें ही लघु उद्योग से संबंधित है जो या तो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उनका विनिर्माण आरक्षित होने अथवा मजबूत लघु उद्योग उत्पाद आधार के कारण है। इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित 57 मदों में से 50 मदें हस्तांतरणीय विशेष आयात लाइसेंसों के प्रति पहले ही आयात योग्य थी।

उदारीकृत आयात नीति का परिणाम लघु क्षेत्र में बनायी जाने वाली अनेक मदों के लिए कच्चे माल इत्यादि की सरलता से उपलब्धता के रूप में सामने आयेगा। और इसके फलस्वरूप, लघु एककों को अपनी उत्पादकता और उत्पाद गुणवत्ता में सुधार के रूप में लाभ पहुंचेगा। इसके कारण अधिक उत्पादकता प्राप्त करने हेतु निपुणता भी हासिल होगी।

(ङ) इन आयातों पर 5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक (मूल) सीमा शुल्क लगाने से इन उद्योगों को आवश्यकतानुसार, सुरक्षा प्राप्त होती है।

Sick PSUs in West Bengal

4345. *SHRI GURUDAS DAS GUPTA*: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) what are the Central Public Sector Undertakings which have fallen sick in West Bengal; and

(b) what steps are being taken for the revival of these units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL) (a) As on 30.6.98, 22 CPSUs having registered office in the State of West Bengal are sick and registered with the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). A list of these units is at the statetment (*see below*)

(b) These CPSUs have been referred to the BIFR for formulation of revival/rehabilitation packages.

Statement

List of BIFR referred Central PSUs having Registered Offices in West Bengal

Sl. No.	Company Name
1.	Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.
2.	Bengal Immunity Ltd.
3.	Bharat Brakes & Valves Ltd.
4.	Bharat Ophthalmic Glass Ltd.
5.	Bharat Process & Mechanical Engineers Ltd.
6.	Biecco Lawrie Ltd.
7.	Braithwaite & Co. Ltd.
8.	Burn Standard Company Ltd.
9.	Cycle Corporation of India Ltd.
10.	Damodar Cement and Slag Ltd.
11.	Eastern Coalfields Ltd.
12.	IISCO Ujjain Pipe & Foundry Co. Ltd.
13.	Indian Iron & Steel Co. Ltd.
14.	Jessop & Co. Ltd.
15.	Mining & Allied Machinery Corpn. Ltd.
16.	National Instruments Ltd.
17.	National Jute Manufacturers Corporation Ltd.
18.	NTC (West Bengal, Assam, Bihar & Orissa) Ltd.
19.	RBL Ltd.
20.	Smith Stanistreet & Pharmaceuticals Ltd.
21.	Tyre Corporation of India Ltd.
22.	Weighbird (India) Ltd.

Meeting on PSUs Disinvestment

4346. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item "Central Unions to meet on PSU disinvestment" published in "Business Standard" dated 7th July, 1998.

(b) if so, whether Government proposes to discuss the issue of disinvestment of PSUs with Central Trade Unions including the Bhartiya Majdoor Sangh (BMS); and

(c) if not, the reasons therefor;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL): (a) Yes Sir.

(b) The Ministry of Finance, the nodal Ministry concerned with disinvestment policy, have not received any proposal from any of the Central Trade Unions for discussing the issue for disinvestment.

(c) Does not arise.

Impact of Economic Sanctions

4347. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government has assessed the impact of Governmental and non-Governmental industry initiatives, like those of Confederation of Indian Industry, in foreign countries to counter the impact of economic sanctions; and

(b) if so, the changes in the policy framework being contemplated especially for countries like United States of America, Japan, United Kingdom etc. to attract more foreign capital and to promote bilateral trade?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The various initiatives taken seem to have had a positive impact. The foreign aid from the World Bank, which had initially be deferred has since been approved. Also, the US Senate has given flexibility to waive the sanctions upto one year.

(b) To promote the flow of foreign capital, various initiatives have been taken by the Government which includes inter alia, allowing unlisted companies to tap overseas market, encouraging foreign direct investment and investment from NRIs/OCBs and FIIs, launching of new India Millennium Scheme by UTI to invite subscription in dollars from NRIs, launching of new Resurgent India Bonds, allowing investment by FII in unlisted domestic debt securities, promoting